International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2024; 7(1): 26-32
www.theeconomicsjournal.com
Received: 16-10-2023
Accepted: 25-11-2023

शबनम भारती
शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, टीएमबीयू, भागलपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शबनम भारती
शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, टीएमबीयू, भागलपुर, बिहार, भारत

भारत में रोजगार और आजीविका को पुनर्जीवित करना: कोविड-19 से पहले और बाद में

शबनम भारती

DOI: https://doi.org/10.33545/26179210.2024.v7.i1.254

सारांश
कोविड ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित किया है। इस मूक आपदा ने दुनिया भर के लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह जैविक आपदा अप्रत्याशित और पूरी तरह से अप्रत्याशित थी।लाखों लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए थे। लगभग 3.3 बिलियन वैश्विक कार्यबल अपनी आजीविका खोने के जोखिम में हैं। जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, भारत को सबसे बड़े संकुचनों में से एक का सामना करना पड़ा है। 2018 में, भारत की जनसंख्या 136.6 करोड़ अनुमानित थी, जिसमें 26% बच्चे (0-14 वर्ष) और 74% वयस्क (15 + वर्ष) शामिल थे। वयस्क आबादी (101 करोड़) में 66% कामकाजी उम्र के लोग (15-59 वर्ष) और 8% वरिष्ठ नागरिक (60 + वर्ष) शामिल हैं। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, लगभग 47 करोड़ (47%) वयस्क देश में काम कर रहे थे। आधे से अधिक (52%) श्रमिक स्व-नियोजित थे, इसके बाद आकस्मिक श्रमिक (24%) और शेष नियमित या वेतनभोगी (24%) थे। इनमें से, आकस्मिक श्रमिक अपने काम की अनियमित प्रकृति और अपने कार्य कार्यक्रम के आधार पर दैनिक मजदूरी भुगतान के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हैं
इस लेख का उद्देश्य भारत में आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए कोविड-19 महामारी के प्रभावों और परिणामों का विश्लेषण करना है। इसका ध्यान दो प्रस्तावों पर केंद्रित है। सबसे पहले, यह तर्क देता है कि जीवन बचाना और आजीविका का संरक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों को एक साथ लेने से लोगों की भलाई को आकार मिलता है, और यह सरकार पर है कि वह इन उद्देश्यों को एक गलत दुविधा पैदा करने वाले या तो विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय इन उद्देश्यों को सुलझाए। दूसरा, इसमें चर्चा की गई है कि कैसे कठोर और लंबे समय तक चले लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया है, जिससे गरीबों पर असमान बोझ पड़ा है, जबकि सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया ने सुधार के कार्य को और भी कठिन बना दिया है।

कुटशब्द : अर्थव्यवस्था, कोविड-19, लॉकडाउन, आजीविका, आपदा

1. प्रस्तावना
भारत की रोजगार चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण आई गहरी मंदी के बीच है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के लिए आर्थिक वृद्धि नकारात्मक रही है और विकास की वार्षिक दर शून्य के करीब रहने की संभावना है।

महामारी से उत्पन्न संकट से पहले भी, अर्थव्यवस्था कई तिमाहियों से धीमी हो रही थी (सुब्रमण्यन और फेलमैन 2019) साहित्य में जिन कारणों की पहचान की गई है उनमें विमुद्रीकरण और जीएसटी के लागू होने जैसे अल्पकालिक झटके, बढ़ती "ट्विन बैलेंस शीट" समस्या और एनपीए संकट सहित मध्यम अवधि के कारक और दीर्घकालिक संरचनात्मक कमजोरियां जैसे खराब बुनियादी ढांचा और आपूर्ति पक्ष पर जटिल नियम और अपर्याप्त रूप से व्यापक आधार वाली घरेलू मांग (समावेशी विकास की कमी) शामिल हैं हालांकि अर्थव्यवस्था अल्पकालिक झटकों (कुछ अनौपचारिक उद्योगों को छोड़कर जो अभी तक जीएसटी-प्रेरित परिवर्तनों से उबर नहीं पाए हैं) से तेजी से उबर रही है, लेकिन मध्यम और दीर्घकालिक कमजोरियां हमारे साथ बनी हुई हैं।

रोजगार के मोर्चे पर, मंदी से पहले, आर्थिक विकास के पैटर्न के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित दीर्घकालिक आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष की समस्याओं ने स्वचालन के बढ़ते दबाव और चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों के साथ कई दशकों के "बेरोजगार विकास" का उत्पादन करने की साजिश रची है। जीडीपी वृद्धि की रोजगार लचीलापन गिर रहा है और 0.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया है। उच्च विकास वर्षों के दौरान, जिन क्षेत्रों ने तेजी से उत्पादन वृद्धि (जैसे वित्त और आईटी-बीपीओ) को प्रेरित किया है, वे बड़े नियोक्ता नहीं थे, और बड़े नियोक्ता (निर्माण के अपवाद के साथ) ने तेजी से उत्पादन वृद्धि नहीं दिखाई (e.g। व्यापार, कपड़ा, परिवहन) हालांकि, चमड़े और जूतों, प्लास्टिक और कपड़ों और बुने हुए कपड़ों जैसे कुछ चमकीले धब्बे हैं। (State of Working India 2018).

दृढ़ विकास पर आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं (मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की कमी और सक्षम नियामक वातावरण) का अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग के लिए गहरा परिणाम पड़ा है।

ऐतिहासिक रूप से, लघु और मध्यम आकार की फर्मों ने अधिकांश देशों में गैर-कृषि रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन का प्रबंधन किया है। भारत में, हालांकि, उत्पादन का प्रमुख पैमाना "नैनो" और "माइक्रो" बना हुआ है, जिसमें औसत फर्म 5 से कम श्रमिकों को रोजगार देती है, और अधिकांश मालिक और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य श्रमिक को रोजगार नहीं देते हैं (बासोल और चांडी 2019) बौनी फर्मों का प्रसार निरंतर अनौपचारिकता (अनिश्चितता) विनियमन की कमी और कम उत्पादकता के लिए स्थितियां पैदा करता है। पर्याप्त गैर-कृषि नौकरियों की कमी ने कृषि अर्थव्यवस्था में संकट में योगदान दिया है, जिसने बदले में कम समग्र मांग की समस्या को और बढ़ा दिया है।

2. मध्यम रोजगार परिदृश्य-2011-2017

2019 की मंदी और महामारी द्वारा दिए गए असाधारण झटके से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग दो दशकों तक मध्यम से उच्च विकास (वास्तविक रूप से प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से अधिक) के चरण का अनुभव किया था। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की कुल रोजगार लोच के साथ रोजगार में काफी धीमी वृद्धि हुई। इस खंड में, हम 2011 और 2017 के बीच की अवधि में समग्र और व्यापक क्षेत्रीय स्तरों पर रोजगार परिदृश्य की संक्षेप में जांच करते हैं। आंकड़ों के मुख्य स्रोत एनएसएसओ रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2011-12) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हैं

2.1 समग्र रुझान

सबसे हाल के उपलब्ध जनसंख्या अनुमानों से पता चलता है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच कामकाजी उम्र की आबादी में 115.5 मिलियन की वृद्धि हुई। लेकिन श्रम बल में केवल 7.7 मिलियन की वृद्धि हुई और वास्तव में कार्यबल में 11.3 मिलियन की कमी आई। (Table 1). इसके परिणामस्वरूप श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के साथ-साथ कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) में बड़ी गिरावट आई और बेरोजगारी दर में नाटकीय वृद्धि हुई (UR). बेरोजगारों की संख्या में 19 मिलियन की वृद्धि हुई, और यूआर में 2.2 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 क्षेत्रीय रुझान

इसके बाद, हम क्षेत्रीय पैटर्न में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले, हम महिला रोजगार में गिरावट की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। जैसा कि तालिका 4 में देखा गया है, ग्रामीण महिलाएं एकमात्र जनसांख्यिकीय समूह हैं जिनमें से कुल कार्यबल वास्तव में 25 वर्ष से अधिक आयु की आबादी के बीच सिकुड़ गया है।

जैसा कि UPSS और UPS परिभाषा में अंतर इंगित करता है, रोजगार में यह गिरावट बड़े पैमाने पर सहायक गतिविधियों में पाई जाती है, i.e. सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक (लेकिन छह महीने से कम) के लिए किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियाँ।

2011-12 और 2017-18 के बीच सहायक गतिविधियों (सहायक गतिविधियों के साथ-साथ एक प्रमुख गतिविधि

में लगी महिलाओं सहित) में शामिल महिलाओं की संख्या में लगभग 32 मिलियन की गिरावट आई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान केवल सहायक गतिविधियों में लगी महिलाओं की कुल संख्या में लगभग 23 मिलियन की गिरावट आई। यह गिरावट महिलाओं द्वारा श्रम बल से बाहर शिक्षा में जाने के कारण नहीं है क्योंकि गिरावट (लगभग 62 प्रतिशत) तीस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में हुई है। रोजगार में यह गिरावट शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ-साथ परिवार की आय में वृद्धि जैसे कारकों के कारण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को कार्यबल से हटा दिया जाता है या काम की उपलब्धता में गिरावट (देशपांडे और कबीर 2019) सहायक गतिविधियों में लगी महिला श्रमिकों की संख्या में अधिकांश गिरावट कृषि क्षेत्र में आई, इसके बाद विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में आई।

2011-12 और 2017-18 के बीच रोजगार की कहानी के संबंध में दो बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले, पुरुषों के लिए, काम करने की उम्र की आबादी में वृद्धि को देखते हुए रोजगार सृजन की गति आवश्यकता से बहुत कम हो गई। दूसरा, पिछले छह वर्षों की नौकरी छूटने की कहानी मुख्य रूप से वृद्ध ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि में सहायक आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के बारे में है।

महिला कृषि रोजगार में यह गिरावट इस क्षेत्र में रोजगार में कुल गिरावट का हिस्सा है, जो 232 मिलियन (कार्यबल का 49 प्रतिशत) से 205 मिलियन (कार्यबल का 44 प्रतिशत) हो गया है जबकि कृषि रोजगार में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है और संरचनात्मक परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी इसका स्वागत किया जाता है, अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस अवधि में विनिर्माण रोजगार में भी 3.5 मिलियन की गिरावट आई है, जिससे कुल कार्यबल में पहले से ही कम हिस्सेदारी 12.6 से घटकर 12.1 प्रतिशत हो गई है। (Mehrotra and Parida 2019).

फिर भी, मध्यम रोजगार परिदृश्य में एक दिलचस्प उज्ज्वल स्थान संगठित विनिर्माण क्षेत्र रहा है। भले ही विनिर्माण में समग्र रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों के अनुसार संगठित क्षेत्र ने इस अवधि में 20 लाख नौकरियों की वृद्धि दर्ज की। बुना हुआ कपड़ा, प्लास्टिक, चमड़ा और जूते जैसे संगठित उद्योगों ने इस अवधि में रोजगार सृजन के साथ-साथ मजदूरी में वृद्धि के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है (Basole and Narayan 2020).

3. कोविड-19 संकट की ओर ले जाने वाला रोजगार परिदृश्य

जैसा कि हमने ऊपर देखा, 2017-18 और 2018-19 के बीच अधिकांश रोजगार संकेतकों में थोड़ा सुधार हुआ। विशेष रूप से, ग्रामीण महिलाओं ने 2011-12 और 2017-18 के बीच खोए हुए रोजगार का अधिकांश हिस्सा हासिल किया। और सभी जनसांख्यिकीय समूहों में नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के अनुपात में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है (rural-urban, male-female). लेकिन फिर भी रोजगार की चुनौती महत्वपूर्ण बनी रही, जैसा कि उच्च युवा बेरोजगारी दर, कम महिला श्रम बल भागीदारी दर और स्वयं के खाते वाले उद्यमों के उच्च अनुपात में देखा गया।

इन दीर्घकालिक समस्याओं के पीछे, कोविड-19 का प्रभाव विनाशकारी रहा है।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल-मई 2020 के दौरान देश भर में अधिकांश क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां रुक गईं। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जो चालू थे, देश भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े व्यवधान थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार अप्रैल और मई 2020 के महीनों में बेरोजगारी दर क्रमशः 23.5 प्रतिशत और 21.7 प्रतिशत रही।

लॉकडाउन के कारण अप्रैल के अंत तक लगभग 17.7 मिलियन वेतनभोगी नौकरियां चली गईं, जो मई में बढ़कर 17.8 मिलियन हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने चल रहे संकट के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है कृषि क्षेत्र के अलावा, जो कुल रोजगार (42.4 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसे "कम जोखिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तीन बड़े नियोक्ता अर्थात् विनिर्माण, निर्माण और व्यापार, होटल और रेस्तरां, जो कुल रोजगार का 36 प्रतिशत हिस्सा हैं, कोविड-19 के झटके का एक महत्वपूर्ण खामियाजा भुगत रहे हैं।

जून में शुरू हुई अर्थव्यवस्था की धीमी शुरुआत के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों और नौकरियों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई। सीएमआईई के आंकड़े भी रिकवरी को दर्शाते हैं।

जून में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 10.2 प्रतिशत हो गई और जुलाई में कोविड से पहले के 7.43 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। लेकिन पुनर्प्राप्ति का मार्ग जटिल और अस्पष्ट बना हुआ है। अगस्त 2020 में बेरोजगारी फिर से बढ़कर 8.35 प्रतिशत हो गई और बाद में इसमें गिरावट आई है।

सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के पहले तीन हफ्तों के लिए औसत श्रम बल भागीदारी दर अगस्त में 41 प्रतिशत की तुलना में 40.7 प्रतिशत थी। इस बार नौकरियों में कमी का कारण ग्रामीण बाजारों में अधिक पाया जा सकता है। वास्तव में, अगस्त के बाद से ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम का नुकसान और खरीफ फसल की बुवाई का अंत है।

कुल मिलाकर, जबकि सबसे बुरा समय समाप्त होने की संभावना है, सुधार की समयरेखा और प्रकृति उद्योगों, भौगोलिक और जनसांख्यिकी में अत्यधिक भिन्न है। यह चिंता एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट में भी प्रतिध्वनित होती है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि अगर वायरस की रोकथाम में छह महीने लगते हैं तो 6.1 मिलियन युवा (15-24 वर्ष) नौकरी खो सकते हैं। इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है जो स्थिति को और खराब कर रहा है।

श्रम बाजार के प्रभाव की सीमा को समझने के लिए एक और पहलू यह है कि सीएमआईई शीर्षक बेरोजगारी डेटा नौकरियों के नुकसान को कम कर सकता है। सर्वेक्षण यह पूछता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी दिए गए संदर्भ दिन या पिछले दिन काम किया था, या यदि नहीं, तो क्या उन्हें निकट भविष्य में काम पर लौटने की उम्मीद है। इस प्रकार, जो व्यक्ति यथोचित रूप से अपनी दुकानों या व्यवसायों का संचालन शुरू करने या अंततः रोजगार के अन्य रूपों में लौटने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई आय अर्जित नहीं कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार के रूप में नहीं गिना जा सकता है, हालांकि उन्हें अभी भी अंतरिम में गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। महामारी की अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में रोजगार के सामान्य उपायों का उपयोग करने में यह एक समस्या है। हम बाद में इस बिंदु पर लौटते हैं।

4. कोविड-19 महामारी का प्रभाव

भारतीय श्रमिकों पर महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अब बड़ी संख्या में लक्षित छोटे सर्वेक्षण उपलब्ध हैं। ये सर्वेक्षण अक्सर राहत देने के दौरान नागरिक समाज संगठनों, अकादमिक शोधकर्ताओं और परामर्श फर्मों द्वारा किए गए हैं। अधिकांश आबादी के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्गों (जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले आदि) के उद्देश्यपूर्ण नमूने पर आधारित हैं।) लगभग सभी नमूने के आकार के साथ टेलीफोनिक सर्वेक्षण हैं जो कुछ सौ से लेकर दसियों हज़ार तक भिन्न होते हैं।

अधिकांश सर्वेक्षण अप्रैल से जुलाई की अवधि में किए गए थे और इसमें तीन व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया थाः रोजगार और आजीविका पर लॉकडाउन का प्रभाव, वित्तीय और खाद्य सुरक्षा पर घरेलू स्तर के प्रभाव और राहत उपायों तक पहुंच। चूंकि अधिकांश सर्वेक्षण उद्देश्यपूर्ण और गैर-यादृच्छिक होते हैं, इसलिए निष्कर्ष केवल नमूने से संबंधित होते हैं और जनसंख्या के लिए सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

4.1 रोजगार पर प्रभाव

भारतीय कार्यबल के एक बड़े हिस्से में अनौपचारिक श्रमिक शामिल हैं, जो या तो स्व-नियोजित हैं या दैनिक मजदूरी और अन्य प्रकार के अल्पकालिक, मौखिक अनुबंधों पर काम करते हैं। आर्थिक गतिविधि रुकने से वे तुरंत बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार, लॉकडाउन के सबसे प्रमुख प्रभावों में से एक बेरोजगारी की दर में अचानक वृद्धि थी।

कोविड प्रभाव सर्वेक्षण आम तौर पर उन श्रमिकों के हिस्से के रूप में रोजगार के नुकसान की मात्रा निर्धारित करते हैं जो लॉकडाउन से पहले कार्यबल में थे, लेकिन या तो बेरोजगार, श्रम बल से बाहर या कार्यबल में थे, लेकिन इस अवधि के दौरान एक भी दिन काम किए बिना।

रोजगार पर कोविड-2019 का प्रभाव तीन प्रमुख सर्वेक्षणों द्वारा प्रदान किया गया है, जिनमें अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय सर्वेक्षण 7 (अप्रैल के मध्य से मई के मध्य तक 5000 से कम उत्तरदाताओं के साथ आयोजित) डालबर्ग सर्वेक्षण 8 (अप्रैल और मई में आयोजित, जिसमें लगभग 25,000 उत्तरदाता थे) और एक्शनएड सर्वेक्षण 9 (मई-जून में आयोजित, जिसमें लगभग 11,537 उत्तरदाता थे) शामिल हैं

विभिन्न नमूना रणनीतियों और भौगोलिक क्षेत्रों के बावजूद, निष्कर्षों में कुछ सहमति है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लॉकडाउन के महीनों के दौरान लगभग 80 प्रतिशत शहरी श्रमिकों ने अपनी आजीविका खो दी।

छोटे, लक्षित सर्वेक्षणों का संचालन जारी है, जिससे हमें ठीक होने की आंशिक तस्वीर मिलती है।

ग्राम-वाणी, एक सामुदायिक मीडिया मंच ने अक्टूबर 2020 में ऑटो, निर्माण और परिधान क्षेत्रों (ज्यादातर एनसीआर क्षेत्र में) में 372 प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण किया और पाया कि 60 प्रतिशत अभी भी काम से बाहर थे।10. कपड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसमें

20 प्रतिशत श्रमिकों ने रुपये से अधिक की आय में कमी की सूचना दी। 2000 प्रति माह।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनौपचारिक श्रमिकों के सर्वेक्षण के दूसरे दौर से पता चला है कि अप्रैल-मई के दौरान काम गंवाने वाले लगभग 20 प्रतिशत श्रमिक अक्टूबर-नवंबर की अवधि में काम से बाहर थे। हालांकि, जिन लोगों को काम मिल सकता था, उनकी कमाई काफी हद तक कोविड से पहले के स्तर तक पहुंच गई थी।

4.2 आय पर प्रभाव

अब हम आय हानि पर कोविड-19 सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण में नमूना आय में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की गिरावट आई। लॉकडाउन के दौरान काम करना जारी रखने वाले आकस्मिक श्रमिकों के लिए, यह काम की उपलब्धता में कमी के साथ-साथ मजदूरी दर में गिरावट का परिणाम था। डालबर्ग सर्वेक्षण में पाया गया है कि जून की शुरुआत में औसत मासिक घरेलू आय ₹9,960 (संकट से पहले) से घटकर ₹4,110 हो गई। मासिक आय में औसतन 65 प्रतिशत की गिरावट आई।

एलएसई-सीईपी सर्वेक्षण में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। भलोटिया एट अल (2020) से पता चलता है कि कम आय वाले चतुर्थांश में श्रमिकों ने बड़ी आय हानि का अनुभव किया।

एन. सी. ए. ई. आर.-डी. सी. वी. टी. एस. सर्वेक्षण ने केवल इस बारे में आंकड़े एकत्र किए कि मई महीने के दौरान आय में बहुत गिरावट आई थी या नहीं। यहां, 85 प्रतिशत परिवारों ने लॉकडाउन से पहले की तुलना में मई में आय में कुछ स्तर की कमी दर्ज की। सर्वेक्षण के अनुसार, वेतनभोगी श्रमिकों के लिए 50 प्रतिशत से कम और किसानों के लिए केवल 30 प्रतिशत से अधिक की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत ने बताया कि आय को "बहुत" नुकसान हुआ है। शहरी परिवार भी प्रमुख रूप से प्रभावित हुए थे और 60 प्रतिशत ने बताया था कि उनकी आय को बहुत नुकसान हुआ था।

ग्रामीण परिवारों के गाँव कनेक्शन सर्वेक्षण में, 71 प्रतिशत ने लॉकडाउन के दौरान मासिक घरेलू आय में गिरावट दर्ज की।

कुल मिलाकर, जो पैटर्न सामने आया है, वह यह है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार और आकस्मिक मजदूरी और अस्थायी वेतनभोगी श्रमिक बहुत अधिक प्रभावित हुए, जिसके बाद स्व-नियोजित लोग आए।

उच्च आय वाले और स्थायी वेतनभोगी कर्मचारी सबसे कम प्रभावित हुए।

आकस्मिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए वसूली अपेक्षाकृत तेज थी, लेकिन कम से कम अगस्त तक, एक महत्वपूर्ण अनुपात काम से बाहर बना रहा। स्व-नियोजित लोगों के संबंध में यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमने कहीं और नोट किया है कि महामारी के दौरान रोजगार को मापना एक चुनौतीपूर्ण मामला है, जिसमें पारंपरिक प्रश्न और श्रेणियां स्थिति को पर्याप्त रूप से पकड़ने में विफल रहती हैं। स्व-नियोजित कर्मचारी तब भी नियोजित होने की सूचना दे सकते हैं जब उनका व्यवसाय नहीं चल रहा हो या कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हो। इसका मतलब है कि वे प्रभावी रूप से बेरोजगार हैं (zero or near-zero earnings). इस प्रकार, रोजगार संख्या इन असामान्य समय में वास्तविक बेरोजगारी की डिग्री को कम कर सकती है।

4.3 एमएसएमई पर असर

घरेलू और उद्यम सर्वेक्षण जैसे ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (गेम) द्वारा 1500 सूक्ष्म उद्यमों का सर्वेक्षण और क्रेया विश्वविद्यालय में लीड; अखिल भारतीय निर्माता संगठन के साथ-साथ कई समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि महामारी के दौरान सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

यह एक तत्काल और साहसिक कार्रवाई की मांग करता है, विशेष रूप से स्पेक्ट्रम के नैनो और सूक्ष्म छोर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये ऐसे उद्यमी हैं जिन्हें औपचारिक ऋण से बाहर रखा गया है। धारा 6 में हम उद्योग सहायक नेटवर्क (यू. एस. ई. एन. ई. टी.) नामक एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि सरकारी पैकेज उन उद्यमों तक पहुँचें जिन्हें संकट से बचने और बाद में पुनर्जीवित होने के लिए समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है।

5. कोविड संकट के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया

इस अभूतपूर्व संकट ने दुनिया भर की सरकारों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। जेंटिलिनी एट अल (2020) इस तरह की राजकोषीय और मौद्रिक प्रतिक्रियाओं की एक "लाइव सूची" संकलित करते हैं। इस खंड में, हम अब तक की भारतीय नीतिगत प्रतिक्रिया की संक्षेप में जांच करते हैं। मार्च के अंत में पहले पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के साथ शुरू होने वाली प्रतिक्रिया कई चरणों में आई है। उसके बाद, आत्मनिर्भर भारत 1,2 और 3 पैकेज के रूप में सहायता की कई किश्तें आई हैं। यहाँ इन उपायों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना उद्देश्य नहीं है। इसके बजाय हम उन उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सीधे

रोजगार सृजन और आजीविका समर्थन से संबंधित हैं। इनमें पीडीएस के तहत खाद्य वितरण में वृद्धि, जन धन खातों में नकद हस्तांतरण, मनरेगा बजट का विस्तार और प्रधानमंत्री रोजगार अभियान शामिल हैं। इसके अलावा, हम एमएसएमई को आपातकालीन ऋण ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के रूप में प्रदान की गई अप्रत्यक्ष सहायता पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं।

यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यहां केंद्रीय स्तर पर योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन विभिन्न राज्यों ने विस्तारित पीडीएस और अतिरिक्त नकद हस्तांतरण के रूप में केंद्र सरकार के उपायों को पूरा किया है।15

समर्थन उपायों की पहुंच पर सर्वेक्षण और प्रशासनिक आंकड़ों में जाने से पहले, हम इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में भारत की प्रत्यक्ष अतिरिक्त राजकोषीय प्रतिक्रिया निम्न स्तर पर बनी हुई है।16यह ज्यादातर राजकोषीय घाटे में वृद्धि और ऋण-से-जीडीपी अनुपात के व्यापक आर्थिक परिणामों के साथ एक चिंता के कारण है जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय होगा। हम अगले खंड में इस मुद्दे को संक्षेप में संबोधित करते हैं।

5.1 पीडीएस और नकद हस्तांतरण

व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर, पिछले खंड में चर्चा किए गए कोविड-19 प्रभाव सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत घोषित अतिरिक्त पात्रता (मूल अनाज भत्ते से 5 किलो अधिक और 1 किलो दाल) के साथ-साथ दालें (मई के मध्य तक) उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने के बाद लाखों परिवारों के बीच खाद्य असुरक्षा में भारी वृद्धि को रोका। चूंकि स्कूल और आंगनवाड़ियां बंद होने के कारण गरीब परिवारों के लिए मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस आधारित विकल्प भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए पीडीएस और भी महत्वपूर्ण हो गया।

जिन लोगों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन. एफ. एस. ए.) राशन कार्ड थे, उनके लिए अतिरिक्त पात्रता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन उन परिवारों तक पहुंचना जो पहले से ही एन. एफ. एस. ए. प्रणाली में नहीं थे, एक अधिक कठिन काम रहा है। राज्य सरकारें संकट से पहले भी लाभार्थियों की अपनी सूचियों के साथ राष्ट्रीय एन. एफ. एस. ए. सूची को पूरक बना रही थीं। जो राज्य स्तरीय कार्ड धारक थे (लेकिन एनएफएसए कार्ड धारक नहीं थे) वे राहत पैकेज के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के आधार पर अतिरिक्त पात्रता प्राप्त करने में सक्षम थे।

5.2 मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार अभियान

महामारी और लॉकडाउन के झटके के तुरंत बाद मनरेगा ने बहुत महत्व हासिल कर लिया। ग्रामीण परिवारों ने प्रवासी प्रेषण से आने वाली आय खो दी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्त पोषण, कुल बजट को 1 लाख करोड़ रुपये तक लाना, इस प्रकार एक स्वागत योग्य कदम था।

पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) द्वारा लॉन्च किए गए मनरेगा ट्रैकर 17 में बताए गए मनरेगा एमआईएस के आंकड़ों से पता चलता है कि यह कार्यक्रम संकट की इस घड़ी में रोजगार सृजन के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभरा है। मनरेगा कार्यों की भारी मांग इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-जून 2020 के बीच 35 लाख नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मनरेगा के तहत रिकॉर्ड संख्या में परिवारों को रोजगार दिया गया है। उदाहरण के लिए, जून 2020 में, मनरेगा के तहत 32.2 मिलियन परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जो जून 2019 की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। (21.6 million). सितंबर-अक्टूबर 2020 तक यह 36.3 मिलियन तक पहुंच गया था कार्यक्रम के तहत रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मनरेगा कार्य के लिए अभी भी काफी मांग पूरी नहीं हुई है। पी. ए. ई. जी. के मनरेगा ट्रैकर ने बताया कि 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम की मांग की है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है. नवंबर 2020 की शुरुआत तक, 19 मिलियन लोग काम की प्रतीक्षा कर रहे थे।

5.3 आपातकालीन ऋण गारंटी योजना

आत्मनिर्भर भारत 1 पैकेज (मई के मध्य) का एक प्रमुख घटक 3 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ आपातकालीन ऋण ऋण गारंटी योजना थी। ऊपर चर्चा किए गए उपायों के विपरीत, यह आसान तरलता के रूप में "रेखा से नीचे" समर्थन था। इसने सरकारी गारंटी के तहत एमएसएमई को 9.25 प्रतिशत पर एक साल की मोहलत के साथ चार साल के ऋण के रूप में एमएसएमई को तरलता सहायता की पेशकश की। हालांकि, परामर्श में, कई एमएसएमई उद्यमियों ने नोट किया कि एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले संसाधनों की कमी की वर्तमान परिस्थितियों में ऋण

प्राप्त करने की शर्त (केवल 29 फरवरी, 2020 तक 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण वाले) कुछ हद तक मनमाना थी। एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि सभी ऋणों को 20-30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए क्योंकि संपार्श्विक पहले से ही उपलब्ध था।

6. निष्कर्ष

हम इस लेख को एक ऐसे खंड के साथ समाप्त करते हैं जो भारत में रोजगार की चुनौती को हल करने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण के लिए अल्पावधि के साथ-साथ दीर्घकालिक में एक संभावित पाठ्यक्रम को चार्ट करता है। जैसा कि परिचय में उल्लेख किया गया है और बीसीजी-सीआईआई रिपोर्ट (भट्टाचार्य और बीजापुरकर 2017) में भी प्रकाश डाला गया है कि रोजगार सृजन के साथ विकास की रणनीति की आवश्यकता है, अकेले विकास पर्याप्त नहीं है। इसमें नए रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण रूप से अधिक संसाधनों का निवेश करना शामिल है और न केवल मौजूदा श्रम को अधिक उत्पादक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

जैसा कि दिखाया गया है, सीएमआईई के आंकड़ों के साथ-साथ अन्य लक्षित सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अधिकांश श्रमिकों (स्व-रोजगार, आकस्मिक और नियमित मजदूरी) के लिए भारी नौकरी और आय का नुकसान हुआ है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए गंभीर प्रभाव के साथ बुरी तरह प्रभावित किया गया है। भले ही, शुक्र है कि आर्थिक सुधार अच्छी तरह से चल रहा है, कम बचत, परिसंपत्तियों की संकटपूर्ण बिक्री और कमजोर परिवारों द्वारा किए गए ऋण में वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभाव होने की संभावना है, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत की प्रत्यक्ष राजकोषीय प्रतिक्रिया (ऋण और अन्य तरलता आधारित उपायों के विपरीत) अब तक मौन रही है, और तुलनात्मक विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है।

यदि हम तत्काल मानवीय संकट के अलावा लाखों कमजोर परिवारों की सहायता के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमें आने वाले वर्षों में दीर्घकालिक मानव पूंजी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह समर्थन बढ़ाए, क्योंकि राज्य, जो लड़ाई में सबसे आगे हैं, उनके पास वह करने के लिए वित्तीय स्थान नहीं है जो आवश्यक है।

7. सन्दर्भ

1. अब्राहम, रोजा और आनंद श्रीवास्तव। 2019 की बात है. उन्होंने कहा, "भारत के श्रम बाजार सर्वेक्षण कितने तुलनात्मक हैं?: एनएसएस, श्रम ब्यूरो और सीएमआईई अनुमानों की तुलना। सतत रोजगार कार्य पत्र #21, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलोर।
2. भट्टाचार्य अरिंदम और अपर्णा बीजापुरकर। 2017 में। भारतः नए वैश्वीकरण में विकास और नौकरियां, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और भारतीय उद्योग का सम्मेलन।
3. कन्नन, के. पी. और जी. रवींद्रन। 2009 में। रोजगार के बिना विकासः भारत के संगठित विनिर्माण में बेरोजगारी वृद्धि की एक चौथाई सदी। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (2009) 80-91।
4. मेहरोत्रा, संतोष और जजती परिदा।2019 की बात है. "भारत का रोजगार संकटः शिक्षा के बढ़ते स्तर और घटती गैर-कृषि रोजगार वृद्धि"। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग पेपर#23, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय।
5. मुरलीधरन, टी, बीनो पॉल और अमित बासोले। 2020. एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन और विस्तार के लिए उद्योग सहायक उद्यम नेटवर्क (यूएसईएनईटी) का निर्माण, सितंबर-अक्टूबर 2020 में रोजगार और कौशल पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को सलाह देने वाला विशेषज्ञ समूह।
6. नाथ परितोष और अमित बासोले। 2020 का आयोजन क्या 2011 और 2017 के बीच भारत में रोजगार में वृद्धि हुई या गिरावट आई? : आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में आने वाले कार्यबल में पूर्ण परिवर्तनों का अनुमान लगाना।
7. रॉड्रिक, डैनी। 2007 में। "एक अर्थशास्त्र कई उपाय-वैश्वीकरण, संस्थान और आर्थिक विकास"। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।